ल.अं./48/एस.एल.बी.सी./452 **19.10.2022**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय/ महोदया,

विषय :- राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की जून 2022 त्रैमासांत की समीक्षा बैठक दिनांक 29.09.2022 का कार्यवृत्त

कृपया दिनांक 29.09.2022 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0) की जून 2022 त्रैमासांत की समीक्षा बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

(संजय कुमार वर्मा)
उप महाप्रबन्धक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, लखनऊ अंचल, "बड़ौदा हाउस", वी–23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Lucknow Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
फोन / Phone : 0522-6677607 (GM), 6677609 (Sectt.), 6677722 (DGM), 6677730 (CM), 6677721, 6677725
ई–मेल / E-mail : slbc.up@bankofbaroda.com, वेबसाइट / Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की जून 2022 तिमाही की दिनांक 29.09.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की जून 2022 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 29.09.2022 को प्रदेश के **माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी** की गरिमामयी उपस्थिती में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता **श्री अजय कुमार खुराना, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई** द्वारा की गयी। इस बैठक मे डॉ0 बालू केनचप्पा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ; श्री आलोक कुमार, आई.ए.एस. सचिव योजना विभाग, उ0प्र0 शासन; श्री प्रांजल यादव, आई.ए.एस. सचिव, एम.एस.एम.ई., उ0प्र0 शासन; श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उ0 प्र0; श्री अनुपम शुक्ला, विशेष सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन; श्री समीर, विशेष सचिव, वित्त उ0प्र0 शासन; श्री संजय कुमार दोरा, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, लखनऊ; सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागो के अधिकारी तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा सहभागिता की गयी। बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ मे **श्री ब्रजेश कुमार सिंह, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0प्र0** ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। अपने स्वागत सम्बोधन में उन्होंने बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग व कार्यों की सराहना की। उन्होंने प्रदेश में की जा रही बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों की अद्यतन प्रगति से सभा को अवगत कराया।

गत बैठक दिनांक 01.07.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि के उपरांत, उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण मानकों पर प्रदेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्नवत प्रस्तुत किया:-

- जून 2022 तक प्रदेश में बैंकों का कुल व्यवसाय रू 21 लाख 19 हज़ार करोड़ रहा है जिसमें से जमा राशि रू. 13.82 लाख करोड़ व अग्रिम रू 7.37 लाख करोड़ है जो जून 2021 की तुलना में क्रमशः 7.91 % व 11.45% अधिक है।

- चालू वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक ऋण योजनांतर्गत आवंटित लक्ष्य रू 294988 करोड़ के सापेक्ष रू 64879 करोड़ का ऋण वितरण करते हुए 22% की उपलब्धि हासिल की गयी है जो जून 2021 की उपलब्धि के सापेक्ष रू. 19,216 करोड़ अधिक है| हमारे प्रदेश में MSME Sector के अन्तर्गत कुल आवंटित लक्ष्य रू. 78,360 करोड़ के सापेक्ष रू 27,294 करोड़ का ऋण वितरण करते हुए 36% की उपलब्धि हासिल की गयी है। साथ ही कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कुल आवंटित लक्ष्य रू. 188571 करोड़ के सापेक्ष रू 34637 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है जो 18.37% की उपलब्धि दर्शाता है।

- पी. एम. स्वनिधि पोर्टल के अनुसार प्रदेश को आवंटित कुल लक्ष्य 8,30,000 के सापेक्ष दिनांक 13.09.2022 तक कुल 9,70,947 एवं 9,39,427 (113%) स्ट्रीट वेन्डर्स को योजनांतर्गत क्रमश: ऋण स्वीकृत एवं वितरण किया जा चुका है।

- वित्तीय वर्ष 2022- 23 के दौरान समस्त हितधारकों के समंवयित प्रयासों से सरकार प्रायोजित विभिन्न रोज़गारपरक योजनाओं यथा प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना आदि में शत प्रतिशत लक्ष्यों को हासिल किया गया है जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु विभिन्न योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भी मैं समस्त बैंकों व अन्य हितधारकों का आह्वाहन करता हूँ।

- वर्तमान में प्रदेश में 1,81,093 बैंकिंग केन्द्रों का विशाल नेटवर्क आम जन तक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहा है जिसमें 19,116 बैंक शाखाएं, 19,259 ए.टी.एम., 32643बी सी सखी एवं 1,10,075 बैंक मित्र शामिल हैं।

- उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा RC Filed cases में Recovery हेतु निरंतर प्रदान किये जा रहे सहयोग हेतु आभार प्रगट करते हुए अनुरोध किया कि सरफेसी के अंतर्गत लम्बित मामलों में वसूली हेतु समस्त सम्बंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें ।

- भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 12.03.2021 से अगस्त 2023 तक "आजादी का अमृत महोत्सव" (Azadi Ka Amrit Mahotsav) अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार 06 जून से 12 जून, 2022 तक "आजादी का अमृत महोत्सव" अभियान के तहत "Iconic Week" मनाया गया | मै आपको बताना चाहता हूं कि इस महोत्सव के दौरान मुख्य रूप से दिनांक 31.05.2022, 06.06.2022, 08.06.2022 एवं 10.06.2022 को कार्यक्रमों का आयोजन किया गया| दिनांक 31.05.2022 को देश के समस्त जनपदो के विभिन्न योजनाओ के कुछ लाभाथियों से माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा शिमला (हिमांचल प्रदेश) से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया गया| दिनांक 06.06.2022 को पूरे देश के 25 जनपदो मे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमे से 2 जनपद यथा अलीगढ़ एवं गोरखपुर हमारे प्रदेश से चयनित किए गए| इस अवसर पर आमजनमानस को आसानी से ऋण मुहैया कराने के उद्देश्य से एक पोर्टल - "जनसमर्थ पोर्टल" की शुरूआत की गई| भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.06.2022 को प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न गतिविधियां यथा ऋण शिविर, जनसुरक्षा नामांकन, वित्तीय साक्षरता, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता, बैंकिंग क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले बैंक शाखाओं/ बैंक मित्र व बैंक कर्मचारियों का सम्मान कार्यक्रम आदि सम्पन्न किया गया|

- जून 2022 को समाप्त तिमाही में प्रदेश का ऋण जमा अनुपात 53.37% रहा है जो गत तिमाही मार्च 2022 के स्तर 52.38% से लगभग 1% अधिक है। प्रदेश में बैकों के कुल अग्रिम के सापेक्ष प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में रू 4.09 लाख करोड़ (56%), MSME क्षेत्र में रू 1.59 लाख करोड़ (21.55%) व कमज़ोर वर्ग में रू. 1.53 लाख करोड़ (21%) अग्रिम रहा है जो RBI के निर्धारित मानक क्रमशः 40%, 20% व 10% से अधिक है।

अंत में उन्होंने पुनः समस्त सहभागियों का धन्यवाद व्यक्त किया।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन मे श्री अजय कुमार खुराना, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सर्वप्रथम प्रदेश के वित्तमंत्री माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का बैठक मे पधार कर अपना मार्गदर्शन देने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त किया| उन्होंने सभा में उपस्थित समस्त सम्मानित सदस्यों का अभिवादन करते हुये अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य की आर्थिक गतिविधियों तथा विभिन्न मानकों में प्रदेश मे हुई प्रगति से सभा को निम्नवत अवगत कराया:-

- कोविड से जूझ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए रूस-यूक्रेन युद्ध ने गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है, युद्ध के कारण आज विश्वभर विशेषकर यूरोपियन देशो में फ्यूल गैस तथा कच्चे तेल के दाम बढे हुए है, साथ ही साथ logistics एवं supply chain भी बुरी तरह से प्रभावित है| |

- हमारे देश कि अर्थव्यवस्था $854.7 billion के साथ आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है| भारतीय रिज़र्व बैंक की Monetory Policy के अनुसार वर्ष 2022-23 में देश की जीडीपी विकास दर 7.2% रहने का अनुमान है, परन्तु अर्थव्यवस्था में तेज़ विकास हेतु "आपूर्ति पक्ष" को सुदृढ़ किये जाने कि त्वरित आवश्यकता महसूस की जा रही है |

- उत्तर प्रदेश वितीय वर्ष 2021-22 में ₹21.74 लाख करोड़ रुपये के Gross State Domestic Product के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा है| जिसने न केवल कोविड महामारी से उत्पन्न परिस्थितियो का डट कर मुकाबला किया है बल्कि इसके कारण उत्पन्न विषम आर्थिक स्थितियों से अपनी सुद्दढ नीतियों के कारण अन्य राज्यों कि अपेक्षा तीव्र गति से विकास कर रहा है |

- प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रयासों जैसे कि U P Investor Summit, Establishment of Defense Corridor, Development of New Expressways, Developing New Airports इत्यादि कार्यक्रमों का ही परिणाम है कि प्रदेश में निवेश व रोजगार के असीम अवसर उत्पन्न हुए है | हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा 3rd Ground Breaking Ceremony का आयोजन किया गया जिसमें रू. 80 हजार करोड़ की नई औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया |

- एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) प्रदेश सरकार कि अनूठी योजना जिसने प्रदेश के पारंपरिक उद्योग धंधो को एक नए पहचान दी है इसकी सार्थकता को देखते हुए भारत सरकार इस योजना को पुरे देश में लागू किये जाने का निर्णय किया गया है | इन प्रयासों के कारण ही विगत 5 वर्षो में प्रदेश के ऋण जमानुपात में 6 प्रतिशत से अधिक कि वृद्धि दर्ज की गयी है ।

- प्रदेश सरकार की दूरदर्शी व सकारात्मक सोच के परिणाम स्वरुप विगत पांच वर्ष में विदेशी निवेशको के द्वारा प्रदेश में ₹50,000 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है ।

- प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंको व् प्रदेश सरकार के निरंतर सहयोग के परिणामस्वरूप प्रदेश का CD Ratio जून 2022 को समाप्त तिमाही में विगत वर्ष की तुलना में 3.29% की वृद्धि दर्ज करते हुये 53.37% के स्तर पर पहुँच गया हैं |

- प्रदेश सरकार की अनूठी व महत्वाकांक्षी योजना "One GP One BC" के अंतर्गत अब तक 29,000 से अधिक BC Sakhi को Onboard किया जा चुका हैं जो विभिन्न ग्राम पंचायतों में घर-घर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रही हैं|

- Atal Pension Yojna के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 66.42 लाख से अधिक लोगो को नामांकित किया जा चुका है। हमारे प्रदेश को सर्वाधिक नामांकन के साथ गत -5- वर्षों से पैन इण्डिया प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है।

- PFRDA द्वारा SLBC (U.P) को गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी उत्कृष्ठ प्रदर्शन हेतु "AWARD OF PAR EXCELLENCE" से सम्मानित किया गया है |

- ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंको द्वारा Mobile Banking, UPI , BHIM, Internet Banking, Debit Card इत्यादि सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जा रही है। बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में Digital माध्यम से लेन-देन के कुल 427 Crore Transactions किये गये थे, वही वितीय वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही में 218 Crore से अधिक Transactions किये जा चुके है| प्रदेश में Digital लेनदेन में निरंतर सराहनीय प्रगति दर्ज हो रही है|

- आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में Credit Outreach Camp का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत बैंको द्वारा कुल रु. 7, 065 करोड़ का ऋण वितरण किया गया।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ०प्र० अंचल कार्यालय (लखनऊ अंचल) ZONAL OFFICE (LUCKNOW ZONE)

- वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जून 2021 को समाप्त तिमाही में MSME के अंतर्गत रू 20,558 करोड़ के सापेक्ष चालू वितीय वर्ष कि सामान अवधि में रू 27,954 करोड़ के ऋण का वितरण किया जा चुका है, जो कि गत वर्ष कि तुलना में रू 7,396 करोड़ अधिक है, जो इस बात का द्योतक है की MSME के अंतर्गत strong credit demand बनी हुई है ।

- उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा की गैर निष्पादित आस्तियों कि संख्या प्रदेश में वितीय संस्थानों के लिए मुख्य चुनौती बनी हुई है विशेष रुप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि ऋण के अंतर्गत अत्यधिक NPA (> 40%) है | जिसका प्रमुख कारण गन्ना कृषकों का चीनी मिल द्वारा भुगतान उनके केसीसी खातो में ना करते हुए अन्य खातो में किया जाना है | उन्होंने अनुरोध किया की गन्ना कृषकों का भुगतान KCC Link खातो में किया जाये ।

(कार्यवाही: संस्थागत वित्त, विभाग)

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदेश में विगत 5 वर्षो से शतप्रतिशत लक्ष्यों कि पूर्ति की जा रही है तथा चालू वितीय वर्ष के दौरान 11.75 लाख खातो में रू7390 करोड़ की धनराशी वितरित की गई है जो गत वित्तीय वर्ष कि समान अवधि के दौरान किये गए 5.94 लाख खातो एवं रू 2864 करोड़ की धनराशी से अधिक है|

- SARFAESI Act के अंतर्गत सभी बैंको के -7099- मामले प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालय में आवश्यक अनुमति हेतु लम्बित है जिनमें से -3858- मामले -60- दिन की अवधि से अधिक समय से लम्बित है।

अंत उन्होने एक बार पुनः माननीय वित्त मंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त किया और साथ ही प्रदेश शासन के समस्त विभागों के प्रमुखों व वरिष्ठ अधिकारीयों को धन्यवाद दिया, और सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

डॉ0 बालू केनचप्पा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का हार्दिक अभिनंदन किया| साथ ही प्रदेश शासन, समस्त बैंको व अन्य वित्त संस्थानों के अधिकारीगणों का अभिवादन करते हुए प्रदेश में बैंकिग विस्तार हेतु किये गए कार्य की सराहना की|

प्रदेश के ऋण जमानुपात के विषय में सभा को अवगत कराते हुए **डॉ0 केनचप्पा** ने कहा कि विगत 8 तिमाही में incremental ऋण जमानुपात में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है, अर्थात जमा राशि के सापेक्ष अग्रिम में वृद्धि दर अधिक दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि ऋण जमानुपात की गणना में NBFC द्वारा दिए गए ऋण को भी सम्मलित करने कि आवश्यकता है|

उन्होंने कहा कि प्रदेश के MSME उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु उनको विभिन्न e-commerce portal से जोड़े जाने की आवश्यकता है|

चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि digital lending frauds रोकने के लिए RBI ने card tokenization व्यवस्था को लागू कर दिया है, इसके अन्तर्गत अब ग्राहक को अपने card के details सम्बंधित website मे store करने कि आवश्यकता नहीं है बल्कि अपने card के सापेक्ष वो एक token नंबर प्राप्त कर उसके द्वारा e-commerce portal से खरीदारी कर सकता है|

बैंकिंग क्षेत्र में Digitization के महत्त्व पर बल देते हुए उन्होने बताया कि Digitization के साथ ही साइबर सुरक्षा एवं ऑनलाइन फ्रॉड की बढ़ती हुई घटनाओ को देखते हुए साइबर सुरक्षा तकनीक से संबन्धित आवश्यक नीति/दिशा निर्देश और सख्त बनाने की आवश्यकता है ताकि आम जन में डिजिटल लेनदेन प्रणाली के प्रति विश्वास उत्पन्न हो और वे सहजतापूर्वक ऑनलाइन लेनदेन कर सके।

डॉ0 केंचप्पा जी ने बताया कि BC Certification से सम्बन्धित सभी बैंको से प्राप्त आंकड़ो से परिलक्षित होता है कि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति अपेक्षाकृत नहीं है| साथ ही कतिपय केन्द्रों पर बी सी करेसपांडेन्ट द्वारा शून्य प्रगति व निष्क्रिय होने के भी मामलें शामिल हैं। उन्होंने सभी बैंको से बी सी करेसपांडेन्ट के कार्यो की समय-समय पर समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया ताकि कार्यक्रम में अपेक्षित प्रगति हासिल की जा सके।

(कार्यवाही: समस्त बैंक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

उन्होने कहा कि बैंकिंग व्यवसाय की नींव बैंक व ग्राहक के परस्पर विश्वास पर आधारित होती है अतः बैंको द्वारा अपने ग्राहको को गुणवत्तापरक सेवा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए एवं उनकी शिकायतों का उपयुक्त व समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए|

श्री आलोक कुमार, आई.ए.एस., सचिव, आयोजना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने पी.पी.टी. के द्वारा प्रस्तुत अपने संबोधन में प्रदेश के C:D ratio, पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न प्रगति मापदंडो में चर्चा की| उन्होंने RBI website पर उपलब्ध दिसम्बर'21 के C:D ratio का संज्ञान लेते हुए कहा कि SLBC द्वारा प्रस्तुत आकड़ो तथा RBI website पर दिए गए C:D प्रतिशत में काफी अंतर है । इस सन्दर्भ में आप ने क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक से उपरोक्त विषय में विधिवत गवेषणा करने हेतु आग्रह किया|

श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, लखनऊ ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का बैठक में पधारने हेतु आभार व्यक्त किया तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का अभिवादन किया| उन्होंने अवगत कराया कि प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में कार्यरत बैंको द्वारा ऋण प्रवाह बढाने हेतु किये जा रहे विभिन्न प्रयासों विशेषकर क्रेडिट आउटरीच कैम्पों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु बैंकों की प्रशंसा की।

गत 5 वर्षों में प्रदेश में 40% से कम ऋण जमानुपात वाले जनपदों की संख्या 18 से घटकर 8 हो गयी है जिसके लिए उन्होंने समस्त बैंको को बधाई दी| साथ ही बैंको से शेष 8 जनपदों, जिनमें से अधिकतर जनपद पूर्वान्चल क्षेत्र के हैं, को भी इस श्रेणी से बाहर लाने हेतु सघन प्रयास किये जाने हेतु आह्वाहन किया तथा प्रदेश के सबसे कम ऋण जमानुपात वाले जनपदों में अधिक से अधिक ऋण वितरण कार्यक्रमों का आयोजन करते ऋण प्रवाह को बढाने पर बल दिया|

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

सभा को अवगत करते हुए उन्होंने कहा की PM SVANidhi में माननीय वित्तमंत्री जी के दिशा निर्देशन में अच्छा कार्य किया गया है| उन्होंने कहा कि Border Area Development हेतु विशेष ध्यान देने कि आवश्यकता है| साथ ही साथ उन्होंने अवगत कराया की बैंकों में NPA की समस्या को गम्भीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिलो के जिलाधिकारियो को बैंकों के साथ समन्वय हेतु निर्देशित किया गया है|

उन्होंने सभी कोआपरेटिव बैंक को ज़ल्दी से ज़ल्दी CBS platform पर onboard किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया |

(कार्यवाही: नाबार्ड)

श्री एस. के. दोरा, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने अपने संबोधन में समस्त सहभागियों का अभिवादन करते हुए प्रदेश में गत कुछ वर्षों में बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह हेतु किये गए कार्य की सराहना की तथा निम्न मुद्दों की और समस्त सभाजनों का ध्यानाकर्षण किया:-

- उन्होने अपने सम्बोधन मे उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का राज्य बनाने हेतु प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने हेतु सभी बैंकर्स को पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु आहवाहन किया|
- प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ग्राउंड लेवल क्रेडिट लगभग रु.0.58 लाख प्रति हेक्टेयर ग्राउंड लेवल क्रेडिट है जबकि कि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में यह रु.1.07 लाख प्रति हेक्टेयर के स्तर पर है एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में यह मात्र रु.0.38 लाख प्रति हेक्टेयर है। अतः प्रदेश के पूर्वी व बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्राउंड लेवल क्रेडिट को और बढ़ाने हेतु आवश्यक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है|

- उन्होने स्वयं सहायता समूह के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बैंको द्वारा स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने की अपार संभावना है परंतु उन्होने बैंको को इस क्षेत्र में होने वाले गैर निस्पदाक आस्तियों के बारे में भी अगाह किया तथा स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषण से पहले अत्यंत सावधानी बरतने पर भी बल दिया।

- उन्होने सूचित किया कि नाबार्ड द्वारा प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंको को रियायती दरों पर रु.7100/- करोंड़ का अल्पकालिक ऋण एवं रु.6000/- करोड़ का ऋण दीर्घकालीन पुनर्वित्त हेतु प्रदान किया हैं साथ ही साथ RIDF & LTIF के तहत रु.2389 करोड़ का ऋण बुनियादी ढ़ाचे के विकास हेतु प्रदान किया है।

- नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश मे लगभग 350 एफपीओ के गठन मे सहयोग किया गया है और उन्हे रु.72/- करोड़ का अनुदान भी विभिन्न विकास कार्यो हेतु प्रदान किया गया है।

- उन्होंने सभा को अवगत करते हुए बतया की देश में 184 जिले को RBI के द्वारा credit deficit की श्रेणी में रखा गया है (वो जिले जिनमे प्रति व्यक्ति priority sector lending ₹6,000 से कम है), जिनमे उत्तर प्रदेश कि 22 जिले शामिल है, उन्होंने इन जिलो में priority sector lending बढ़ाने पर बल दिया।

- उन्होंने कहा की आज समय कि आवश्यकता है की Green Financing को बढ़ावा दिया जाये जिसके अन्तर्गत organic farming, solar energy pump sets, wind mills, bio gas plants आदि में फाइनैन्सिंग बढ़ाने की ज़रुरत है।

श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के विकास में बैंकों की महती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए सभा में उपस्थित प्रदेश सरकार एवं बैंको के वरिष्ठ अधिकारीगण, को समीक्षा बैठक में निम्नवत सम्बोधित किया:

- एमएसएमई सेक्टर प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक सशक्त माध्यम है। अतः इस क्षेत्र से सम्बन्धित सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा अधिक से अधिक वित्त पोषण की आवश्यकता है।

- सरकार द्वारा पी.एम. स्वनिधि योजनांतर्गत प्रदेश में अच्छा कार्य किया गया है| साथ ही समस्त बैंकों द्वारा शीघ्रातिशीघ्र वितरण हेतु लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया| **(कार्यवाही: समस्त बैंक)**

- राज्य सरकार किसानों के कल्याण एवं उनके आर्थिक समृद्धि के लिए कृत संकल्पित है। किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी किए जाने के संकल्प की पूर्ति हेतु कृषि, उद्यम, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेरी, आदि को प्रोत्साहित करते हुए किसानों की समृद्धि के उद्देश्य से कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा बैंकों द्वारा इस क्षेत्र को वांछित सहयोग अपेक्षित है।
- उन्होंने समस्त बैंकों का अधिकाधिक स्वयं सहायता समूहों को लिकेंज प्रदान करने हेतु आह्वान किया।
- सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा अधिकाधिक लोगों को लाभान्वयित किया जाना चाहिए तथा लम्बित आवेदन पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करने हेतु बैंकों को निर्देशित किया।
- प्रदेश के ऋण जमा अनुपात को राष्ट्रीय औसत तक पहुँचाने हेतु अपार संभावनाएं मौजूद हैं जिनके बेहतर प्रबन्धन की आवश्यकता है। प्रदेश के पूर्वी जनपदों के ऋण जमानुपात के स्तर चिंता का विषय है|। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र के जनपदों के ऋण जमानुपात को प्रदेश स्तर पर लाने हेतु ऋण शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि अधिकाधिक लोगों को ऋण प्रदान कर लाभांवित किया जा सके व इन जनपदों के साथ-साथ प्रदेश के ऋण जमानुपात में भी बढोत्तरी सम्भव हो सके।

(कार्यवाही: समस्त बैंक व यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया: समंवयक, ऋण जमानुपात हेतु उप-समिति)

- उन्होंने कहा कि सभी बैंक अच्छे ऋण आवेदनों को लम्बित ना रखते हुए उनका निस्तारण ज़ल्द से जल्द किया करे।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

अंत में उन्होंने सभी हितधारकों को समंवित रूप से प्रदेश के ऋण जमा अनुपात को अखिल भारतीय स्तर पर लाने तथा आम जन तक सुलभतापूर्वक ऋण सुविधा पहुँचाने हेतु प्रयास करने का आहवाहन किया ताकि देश की विकास गाथा में हमारा प्रदेश अहम भूमिका का निर्वहन कर सके, तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित $1 trillion के लक्ष्य को ज़ल्द से ज़ल्द प्राप्त करें।

बैठक के अंत में **श्री ब्रजेश कुमार सिंह, महाप्रबन्धक एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,उ0प्र0** द्वारा बैठक मे पधारने के लिए श्री सुरेश कुमार खन्ना, माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश का विशेष आभार व्यक्त किया गया तथा उनके अमूल्य मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद दिया गया। उन्होंने प्रदेश शासन के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों तथा बैंको से पधारे स्टेट प्रमुख व अन्य समस्त सहभागियों का भी आभार व्यक्त किया जिनके सहयोग से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक संपन्न की जा सकी।

****